आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब में ग्रामीण विकास योजनाएं

14. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब में इस प्रयोजनार्थ जिला-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) क्या आवंटित धनराशि का पंजाब सरकार द्वारा सही उपयोग किया जा रहा है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री वाई० के० नायडू): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योनजाओं जैसे (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (2) जवाहर रोजगार योजना, (3) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को मुहैया की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता की कुल राशि को अनुपत्र में दिया गया है **[देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं० 4]** तथा आठवीं योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण रोजगार योजनाएं जैसे जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना और दस लाख कुंओं की योजना के अन्तर्गत पंजाब में जिलेवार आवंटित कुल राशि को अनुपत्र में दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं० 5]** त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलेवार आवंटन नहीं किया जा रहा है।

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवंटित निधियों का उपयोग ठीक प्रकार से हो रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के ध्यान में कोई दुरुपयोग का मामला नहीं आया है।

Problems faced by the Shipping Industry

15. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the present and projected share of shipping industry in transportation of goods;

(b) the details of major problems being faced by the shipping industry; and

(c) the steps proposed to be taken to resolve the problems?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) About 95% of India's overseas trade in terms of volume is moved by sea. The present share of the Indian shipping industry is around 28.7% (provisional) during the year 1994-95 as compared to 33.6% during 1993-94. The projected target of Indian shipping lines share is 40%.

(b) and (c) The major problems being faced by shipping industry both in Public and Private Sector as projected by the Indian National Shipowners' Association (INSA) are as under:—

(i) Separate allocation of External Commercial Borrowings (ECB) for acquisition of ships for boosting of National Shipping Tonnage.

(ii) Enhancement of depreciation from 20% to 25% of cost of the ships on written down value basis.

(iii) Exemption from interest tax on domestic borrowings for acquisition of ships.

(iv) Exemption from customs duty on imported spares and stores for use of coastal ships.

(v) Amendment to Section 76 of the Merchant Shipping Act to give enabling powers to the Director General of Shipping to specify manning scale ' for different categories of ships on the basis of various International Convention and Practices.

(vi) Income Tax Relief to Indian Seafarers in respect of their earning during their service of Articles on Indian ships irrespective of the area of operation of vessels or period of service.

This Ministry has been taking up the issues with the concerned Ministries. In addition, the Government has set up a Committee under the aegis of the National Shipping Board to look into the various requirements of the shipping industry and to furnish their recommendations to the Government by October, 1996.